International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)

E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

# राजस्थान सरकार की कौशल विकास योजनाओं का मानव संसाधन विकास में योगदान: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

**Yogesh kumar[1], Dr. Mini Amit Arrawatia[2]**

[1]Research Scholar, [2]Professor
Department of Commerce & Management
Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur

## सार (Abstract)

मानव संसाधन विकास (Human Resource Development) किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति का आधार होता है। राजस्थान सरकार ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने, कौशल उन्नयन तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कौशल विकास योजनाओं को लागू किया है। इस शोध पत्र का उद्देश्य इन योजनाओं के माध्यम से मानव संसाधन के विकास में हुए योगदान का विश्लेषण करना है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कौशल विकास योजनाओं ने रोजगार, उत्पादकता और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किन्तु क्रियान्वयन की चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।

## 1. प्रस्तावना (Introduction)

आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था ज्ञान, तकनीक और नवाचार पर आधारित होती जा रही है, जहाँ केवल पारंपरिक शिक्षा मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। वर्तमान समय में उद्योगों, सेवा क्षेत्रों तथा उद्यमिता के विविध आयामों में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक कौशल (Practical Skills), तकनीकी दक्षता तथा अनुकूलनशीलता (Adaptability) अत्यंत आवश्यक हो गई है। इसी संदर्भ में मानव संसाधन विकास (Human Resource Development) का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र या राज्य की आर्थिक प्रगति उसके कुशल, प्रशिक्षित और उत्पादक मानव संसाधनों पर निर्भर करती है।

भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ युवा जनसंख्या का अनुपात अत्यधिक है, कौशल विकास एक महत्वपूर्ण नीति-उपकरण के रूप में उभर कर सामने आया है। यदि इस युवा शक्ति को उपयुक्त प्रशिक्षण एवं रोजगारपरक कौशल प्रदान किया जाए, तो यह जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) के रूप में देश की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान कर सकता है। इसके विपरीत, यदि युवाओं को उचित कौशल नहीं मिल पाता, तो बेरोजगारी, अल्परोजगारी और सामाजिक असंतुलन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

राजस्थान, जो भौगोलिक दृष्टि से भारत का एक विशाल राज्य है, विविध सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से युक्त है। यहाँ ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक आजीविकाओं पर निर्भर रहा है, जिससे आधुनिक औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सीमित रही है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कौशल विकास को अपनी विकास नीतियों के केंद्र में स्थान दिया है। इस दिशा में वर्ष 2015 में Department of Skill, Employment and Entrepreneurship की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण, रोजगार सृजन तथा उद्यमिता विकास को एकीकृत करना था।

राजस्थान सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण, निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी, तकनीकी संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा विभिन्न लक्षित वर्गों (जैसे महिलाएँ, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक एवं ग्रामीण युवा) के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। इन प्रयासों के माध्यम से राज्य सरकार न केवल युवाओं की रोजगार क्षमता (Employability) को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार एवं उद्यमिता की ओर भी प्रेरित कर रही है।

कौशल विकास योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य "स्किल गैप" (Skill Gap) को कम करना है, जो शिक्षा प्रणाली और उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच मौजूद होता है। इस अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है कि वे बाजार की मांग के अनुरूप हों। इसके अतिरिक्त, डिजिटल कौशल, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाएँ और पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे युवाओं को भविष्य के रोजगार अवसरों के लिए तैयार किया जा सके।

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ—जैसे रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण कौशल विकास योजनाएँ तथा उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम—राज्य के मानव संसाधन को अधिक उत्पादक, आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है, बल्कि सामाजिक समावेशन (Social Inclusion) और आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) को भी बढ़ावा मिल रहा है।

इस प्रकार, राजस्थान में कौशल विकास की पहलें केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे व्यापक मानव संसाधन विकास की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। यह अध्ययन इसी संदर्भ में यह विश्लेषण करने का प्रयास करता है कि राज्य सरकार की कौशल विकास योजनाएँ किस प्रकार मानव संसाधन के गुणात्मक और मात्रात्मक विकास में योगदान दे रही हैं, तथा इनके माध्यम से राज्य की आर्थिक और सामाजिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा है।

## 2. अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- राजस्थान की प्रमुख कौशल विकास योजनाओं का अध्ययन करना
- इन योजनाओं के माध्यम से मानव संसाधन विकास पर प्रभाव का विश्लेषण करना
- रोजगार एवं स्वरोजगार में योगदान का मूल्यांकन करना
- योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना

## 3. परिकल्पनाएँ (Hypothesis)

इस अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ (Hypotheses) निर्धारित की गई हैं—

1. **$H_{11}$:** कौशल विकास योजनाओं और रोजगार सृजन के बीच सकारात्मक संबंध है।
2. **$H_{12}$:** कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं की तकनीकी दक्षता में वृद्धि करते हैं।
3. **$H_{13}$:** कौशल विकास योजनाएँ स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देती हैं।
4. **$H_{14}$:** कौशल विकास योजनाएँ सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ करती हैं।
5. **$H_{15}$:** कौशल विकास योजनाओं से औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि होती है।
6. **$H_{16}$:** कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता और रोजगार परिणामों के बीच सकारात्मक संबंध है।

इन परिकल्पनाओं के माध्यम से यह अध्ययन यह जांचने का प्रयास करता है कि कौशल विकास योजनाएँ वास्तव में मानव संसाधन के गुणात्मक और मात्रात्मक विकास में कितनी प्रभावी हैं। यह शोध न केवल योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है, बल्कि भविष्य में नीति निर्माण के लिए उपयोगी सुझाव भी प्रदान करता है।

## 4. अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन "राजस्थान सरकार की कौशल विकास योजनाओं का मानव संसाधन विकास में योगदान" विषय पर आधारित एक विश्लेषणात्मक (Analytical) एवं वर्णनात्मक (Descriptive) प्रकृति का शोध है। इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव, उपयोगिता तथा उनकी भूमिका का समग्र मूल्यांकन करना है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आंकड़ों (Secondary Data) पर आधारित है, जिनका संग्रह विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से किया गया है।

द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत राज्य एवं केंद्र सरकार की आधिकारिक रिपोर्टें, नीति दस्तावेज, वार्षिक प्रतिवेदन, योजना से संबंधित प्रकाशन, तथा विभिन्न संस्थानों द्वारा जारी सांख्यिकीय विवरणों का उपयोग किया गया है। विशेष रूप से Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation तथा Department of Skill, Employment and Entrepreneurship के आधिकारिक पोर्टलों एवं प्रकाशनों से प्राप्त जानकारी इस अध्ययन का प्रमुख आधार रही है। इसके अतिरिक्त, National Skill Development Corporation, नीति आयोग, तथा अन्य संबंधित संस्थानों की रिपोर्टों का भी संदर्भ लिया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त डेटा का विश्लेषण गुणात्मक (Qualitative) पद्धति के माध्यम से किया गया है, जिसमें विभिन्न योजनाओं की संरचना, उद्देश्य, क्रियान्वयन प्रक्रिया तथा उनके परिणामों का तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक अध्ययन किया गया है। साथ ही, विभिन्न शोध-पत्रों, जर्नल लेखों एवं समाचार स्रोतों के माध्यम से प्राप्त तथ्यों का आलोचनात्मक (Critical) विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए हैं।

इस शोध में किसी प्राथमिक सर्वेक्षण (Primary Survey) या फील्ड वर्क का समावेश नहीं किया गया है, अतः अध्ययन की प्रकृति दस्तावेजीय विश्लेषण (Documentary Analysis) पर आधारित है। तथापि, डेटा की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए केवल मान्य एवं आधिकारिक स्रोतों को ही शामिल किया गया है।

अध्ययन की सीमा (Scope) राजस्थान राज्य तक सीमित है तथा इसमें मुख्य रूप से उन योजनाओं का विश्लेषण किया गया है जो कौशल विकास एवं रोजगार सृजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, अध्ययन का कालखंड मुख्यतः वर्ष 2015 के पश्चात का रखा गया है, क्योंकि इसी अवधि में राज्य में कौशल विकास के क्षेत्र में संस्थागत एवं नीतिगत स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

इस प्रकार, यह अनुसंधान पद्धति कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव का समग्र एवं यथार्थपरक विश्लेषण प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होती है, जिससे मानव संसाधन विकास में उनके योगदान को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

## 5. डेटा सारणियाँ (Data Tables)

इस अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव को समझने हेतु निम्नलिखित सारणियाँ प्रस्तुत की गई हैं। ये सारणियाँ योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं, रोजगार दर तथा विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के वितरण को स्पष्ट करती हैं।

**सारणी 1: राजस्थान में कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या**

| वर्ष | प्रशिक्षित युवाओं की संख्या | रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या | रोजगार प्रतिशत (%) |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | 1,50,000 | 90,000 | 60% |
| 2019-20 | 1,80,000 | 1,10,000 | 61% |
| 2020-21 | 1,20,000 | 70,000 | 58% |
| 2021-22 | 2,00,000 | 1,30,000 | 65% |
| 2022-23 | 2,50,000 | 1,75,000 | 70% |

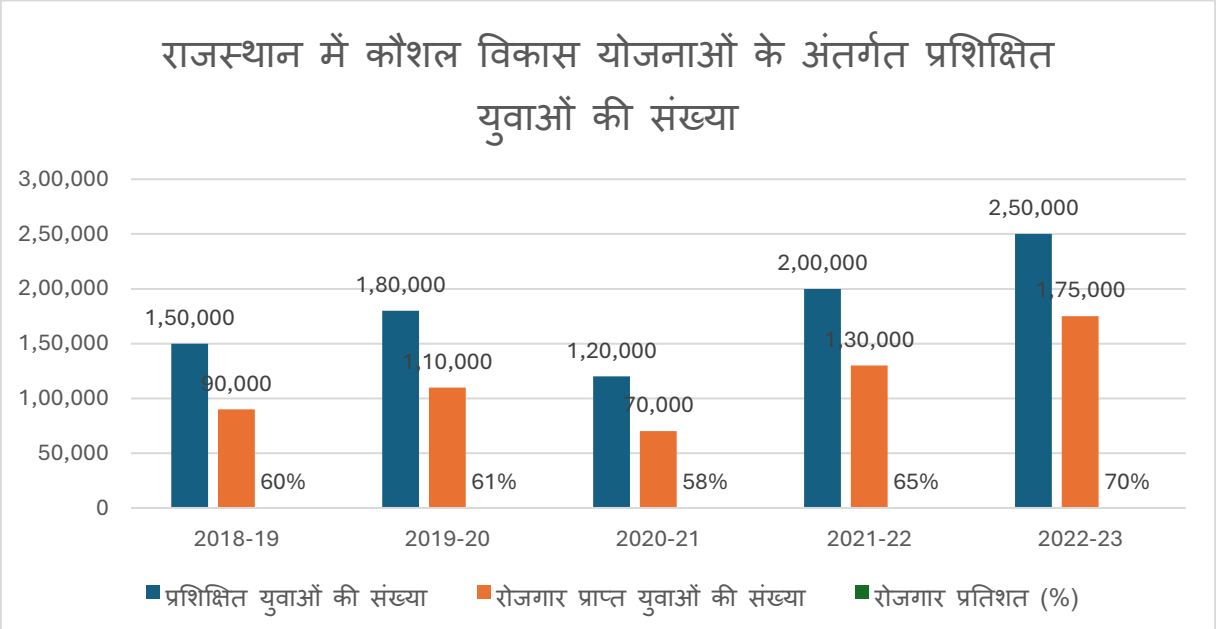


**विश्लेषण:**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में प्रशिक्षण एवं रोजगार दोनों में वृद्धि हुई है, जो कौशल विकास योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

**सारणी 2: विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण का वितरण (प्रतिशत में)**

| क्षेत्र (Sector) | प्रशिक्षण प्रतिशत (%) |
|---|---|
| आईटी एवं डिजिटल | 20% |
| ऑटोमोबाइल | 15% |
| हेल्थकेयर | 12% |
| निर्माण (Construction) | 18% |
| रिटेल | 10% |
| पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी | 15% |
| अन्य | 10% |

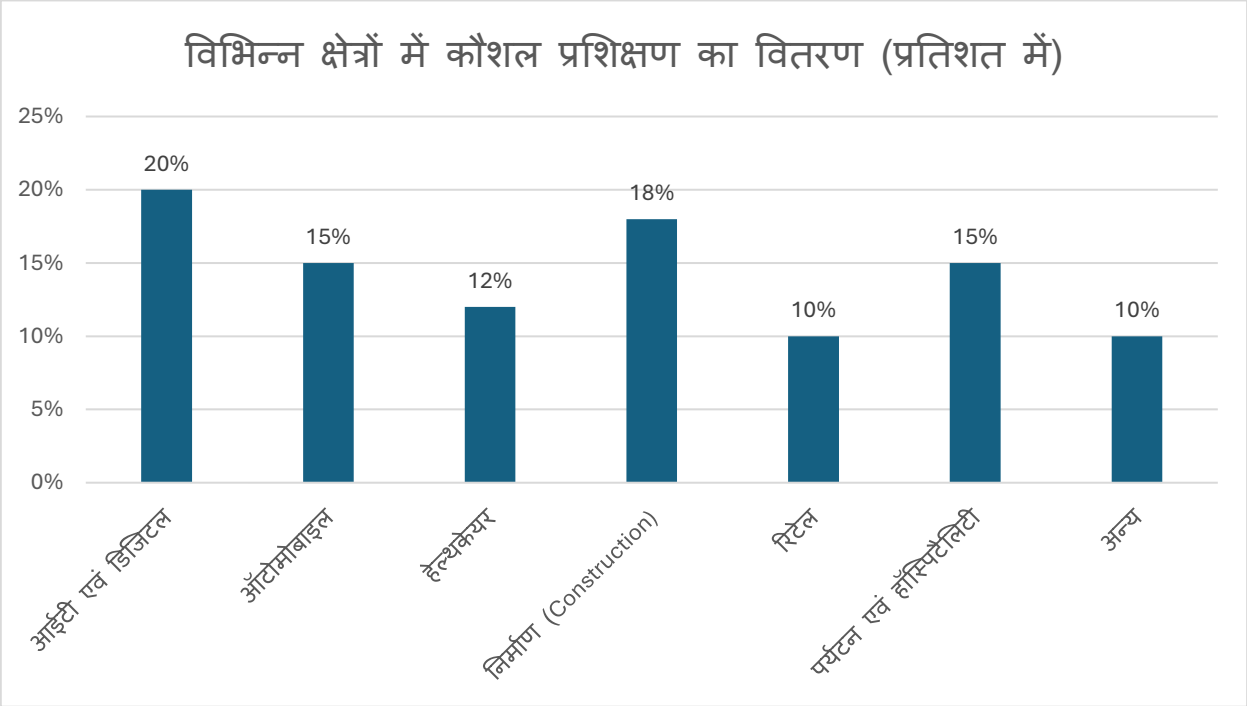


**विश्लेषण:**

यह सारणी दर्शाती है कि आईटी, निर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अधिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो वर्तमान रोजगार बाजार की मांग को प्रतिबिंबित करता है।

**सारणी 3: सामाजिक वर्ग के अनुसार लाभार्थियों का वितरण (प्रतिशत में)**

| वर्ग | प्रतिशत (%) |
|---|---|
| सामान्य वर्ग | 30% |
| अनुसूचित जाति (SC) | 20% |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 15% |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 25% |
| महिलाएँ (सभी वर्गों में) | 35% |

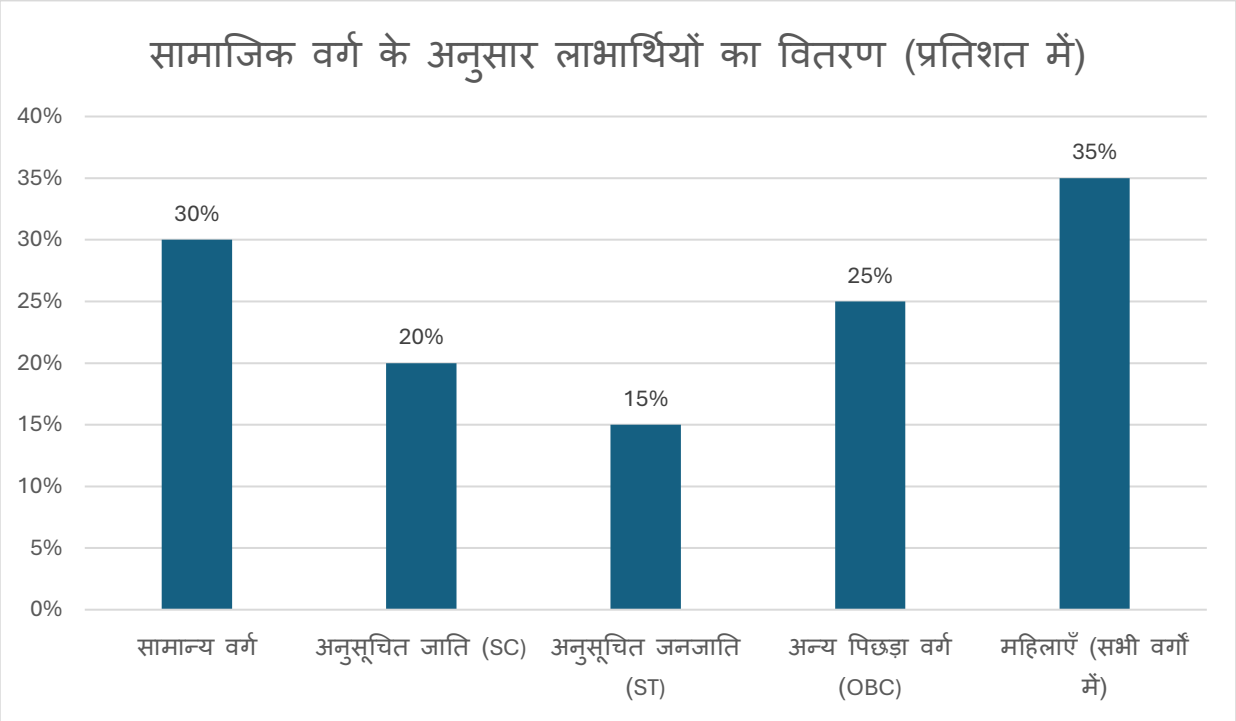


**विश्लेषण:**

इस सारणी से यह स्पष्ट होता है कि योजनाएँ सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दे रही हैं, विशेषकर महिलाओं और पिछड़े वर्गों की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

### 6. राजस्थान में कौशल विकास का संस्थागत ढाँचा

राजस्थान में कौशल विकास को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए एक संगठित एवं बहु-स्तरीय संस्थागत ढाँचा विकसित किया गया है, जिसमें विभिन्न सरकारी संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह संस्थागत व्यवस्था राज्य में कौशल प्रशिक्षण, रोजगार सृजन तथा उद्यमिता विकास के बीच समन्वय स्थापित करती है, जिससे मानव संसाधन का समग्र विकास संभव हो पाता है।

इस ढाँचे का प्रमुख आधार Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation है, जिसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। RSLDC राज्य में विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन एवं समन्वय करता है। यह संस्थान निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं (Training Partners) के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से अल्पशिक्षित, बेरोजगार एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। RSLDC न केवल प्रशिक्षण प्रदान करता है, बल्कि प्रशिक्षण के पश्चात रोजगार से जोड़ने (Placement) की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभाता है, जो इसे अन्य संस्थानों से विशिष्ट बनाता है।

दूसरा महत्वपूर्ण संस्थान Regional Directorate of Skill Development & Entrepreneurship है, जो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है और राज्य में कौशल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करता है। RDSDE का मुख्य कार्य विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को राज्य स्तर पर लागू करना, प्रशिक्षण मानकों को सुनिश्चित करना तथा कौशल विकास की गुणवत्ता को बनाए रखना है। यह संस्थान उद्योगों एवं प्रशिक्षण केंद्रों के बीच समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण की प्रासंगिकता (Relevance) को बढ़ाता है।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज कौशल विकास के पारंपरिक एवं तकनीकी आधार स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। ITI संस्थान युवाओं को विभिन्न ट्रेडों—जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक, वेल्डर आदि—में व्यावसायिक

प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जबकि पॉलिटेक्निक कॉलेज तकनीकी शिक्षा के माध्यम से इंजीनियरिंग एवं तकनीकी क्षेत्रों में दक्षता विकसित करते हैं। ये संस्थान न केवल तकनीकी ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण (Hands-on Training) के माध्यम से छात्रों को उद्योगों के लिए तैयार करते हैं।

राजस्थान सरकार ने इन संस्थानों के आधुनिकीकरण, पाठ्यक्रमों के अद्यतन (Curriculum Update) तथा उद्योगों के साथ साझेदारी को भी बढ़ावा दिया है, ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रासंगिकता सुनिश्चित की जा सके। "ड्यूल ट्रेनिंग सिस्टम" (Dual Training System) जैसे मॉडल के माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षण के साथ-साथ उद्योगों में कार्य अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है।

इस प्रकार, राजस्थान का कौशल विकास संस्थागत ढाँचा एक समन्वित प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसमें विभिन्न संस्थान मिलकर युवाओं को कौशलयुक्त, सक्षम एवं रोजगारोन्मुख बनाने में योगदान देते हैं। यह ढाँचा न केवल राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक समावेशन एवं क्षेत्रीय संतुलन को भी सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होता है।

## 7. राजस्थान सरकार की प्रमुख कौशल विकास योजनाएँ

राजस्थान सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करने, उनकी उत्पादकता बढ़ाने तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक कौशल विकास योजनाएँ संचालित की हैं। ये योजनाएँ न केवल प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, बल्कि प्रशिक्षण के पश्चात रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से भी जोड़ती हैं। निम्नलिखित प्रमुख योजनाएँ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं—

**(i) Employment Linked Skill Training Programme (ELSTP):** Employment Linked Skill Training Programme (ELSTP) का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप अल्पकालिक (Short-term) कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना की विशेषता यह है कि इसमें प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार सुनिश्चित करने (Placement Linked Training) पर विशेष बल दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदाताओं (Training Partners) को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्राप्त हो। विभिन्न सेक्टरों—जैसे रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर, कंस्ट्रक्शन एवं आईटी—में प्रशिक्षण देकर युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जाता है। इस योजना ने राज्य में युवाओं की रोजगार क्षमता (Employability) को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

**(ii) Regular Skill Training Programme (RSTP):** Regular Skill Training Programme (RSTP) का उद्देश्य दीर्घकालिक कौशल विकास को बढ़ावा देना है, जिससे युवा न केवल रोजगार प्राप्त कर सकें, बल्कि स्वरोजगार (Self-employment) के अवसर भी विकसित कर सकें। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी एवं वेलनेस, हस्तशिल्प, कंप्यूटर कौशल आदि शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से सामाजिक समावेशन (Social Inclusion) को भी बढ़ावा मिला है, जिससे वंचित वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

**(iii) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY):** Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्थायी रोजगार से जोड़ना है।: राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत अनेक प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ युवाओं को विभिन्न तकनीकी एवं सेवा क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना की विशेषता यह है कि इसमें प्लेसमेंट आधारित प्रशिक्षण (Placement-oriented Training) पर जोर दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के बाद रोजगार सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। यह योजना ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने तथा पलायन (Migration) को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध हो रही है।

**(iv) मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना:** मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर

वर्गों, महिलाओं तथा पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय उद्योगों एवं पारंपरिक व्यवसायों को भी शामिल किया गया है, जिससे क्षेत्रीय रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलता है। यह योजना न केवल रोजगार सृजन में सहायक है, बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करती है।

**(v) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana भारत सरकार की प्रमुख कौशल विकास योजना है, जिसे राजस्थान में व्यापक रूप से लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों—जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, हेल्थकेयर, रिटेल आदि—में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात युवाओं को प्रमाणपत्र (Certification) प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ती है। PMKVY ने राज्य में कौशल प्रशिक्षण की पहुँच को व्यापक बनाया है और बड़ी संख्या में युवाओं को लाभान्वित किया है।

**(vi) राजस्थान कौशल विकास नीति 2025:** Rajasthan Skill Development Policy 2025 राज्य की एक दूरदर्शी नीति है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास को एक संगठित एवं दीर्घकालिक ढाँचे में विकसित करना है। इस नीति के अंतर्गत उद्योगों के साथ साझेदारी, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, डिजिटल कौशल का विकास, तथा नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह नीति राज्य में "Skill Ecosystem" को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में सहायक है।

उपरोक्त सभी योजनाएँ मिलकर राजस्थान में एक व्यापक कौशल विकास तंत्र (Skill Development Framework) का निर्माण करती हैं। ये योजनाएँ न केवल युवाओं को तकनीकी दक्षता प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, उद्यमशील एवं प्रतिस्पर्धी बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार, राजस्थान सरकार की कौशल विकास योजनाएँ मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में एक मजबूत आधार तैयार कर रही हैं, जो राज्य के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है।

## 8. मानव संसाधन विकास में योगदान (Contribution to HRD)

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजनाओं ने मानव संसाधन विकास (Human Resource Development) के विभिन्न आयामों पर व्यापक और सकारात्मक प्रभाव डाला है। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य के युवाओं को न केवल रोजगारपरक कौशल प्राप्त हो रहे हैं, बल्कि उनकी उत्पादकता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता भी बढ़ रही है। इन योगदानों का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है—

**(i) रोजगार सृजन में वृद्धि:** कौशल विकास योजनाओं का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगार सृजन के रूप में देखने को मिलता है। उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किए जाने से युवाओं की रोजगार क्षमता (Employability) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana तथा Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana जैसी योजनाओं के माध्यम से हजारों युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इससे राज्य में बेरोजगारी दर को नियंत्रित करने में सहायता मिली है तथा युवाओं को स्थायी आजीविका के अवसर प्राप्त हुए हैं।

**(ii) कौशल उन्नयन (Skill Enhancement):** इन योजनाओं के अंतर्गत युवाओं को आधुनिक और बाजारोन्मुख कौशल प्रदान किए जा रहे हैं, जो उन्हें बदलते औद्योगिक परिवेश के अनुरूप सक्षम बनाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (IT), ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर, निर्माण (Construction), रिटेल तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इससे युवाओं की तकनीकी दक्षता (Technical Competency) में वृद्धि हुई है और वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बने हैं।

**(iii) उद्यमिता का विकास (Entrepreneurship Development):** कौशल विकास योजनाएँ केवल रोजगार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वरोजगार और उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करती हैं। विशेष रूप से RSTP जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को बढ़ावा मिला है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। उद्यमिता के विकास से आर्थिक आत्मनिर्भरता (Economic Self-reliance) को भी बल मिला है।

**(iv) सामाजिक समावेशन (Social Inclusion):** राजस्थान की कौशल विकास योजनाएँ सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा ग्रामीण युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इससे समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिला है। महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ी है, जिससे लैंगिक समानता (Gender Equality) को भी प्रोत्साहन मिला है।

**(v) औद्योगिक विकास में योगदान (Industrial Development):** कुशल मानव संसाधन किसी भी औद्योगिक विकास का आधार होता है। कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों को प्रशिक्षित एवं दक्ष श्रमिक उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे उनकी उत्पादकता (Productivity) और प्रतिस्पर्धात्मकता (Competitiveness) में वृद्धि हुई है। इससे राज्य में निवेश को भी प्रोत्साहन मिला है तथा औद्योगिक विकास की गति तेज हुई है। उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच बढ़ते सहयोग से "Industry-Academia Linkage" मजबूत हुआ है, जो दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक है।

## 9. हाल के विकास (Recent Developments) –

राजस्थान में कौशल विकास के क्षेत्र में हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं, जो इस क्षेत्र को और अधिक सशक्त बना रही हैं। हाल ही में राज्य ने PM-SETU योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक उपकरणों की स्थापना, डिजिटल प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास तथा उद्योगों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और छात्रों को व्यावहारिक एवं उद्योगोन्मुख अनुभव प्राप्त हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित Rajasthan Youth Policy 2026 युवाओं के समग्र विकास पर केंद्रित है, जिसमें कौशल आधारित शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, खेलकूद तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह नीति कौशल विकास को शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने का प्रयास करती है, जिससे युवाओं को प्रारंभिक स्तर से ही रोजगारपरक कौशल प्राप्त हो सके।

इसके साथ ही, डिजिटल स्किलिंग (Digital Skilling), स्टार्टअप प्रोत्साहन (Startup Promotion) तथा हरित कौशल (Green Skills) जैसे नए क्षेत्रों पर भी राज्य सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे न केवल पारंपरिक क्षेत्रों में, बल्कि उभरते हुए क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

समग्र रूप से देखा जाए तो हाल के विकास यह दर्शाते हैं कि राजस्थान सरकार कौशल विकास को एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में अपनाते हुए इसे राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के केंद्र में स्थापित कर रही है।

## 10. चुनौतियाँ (Challenges)

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजनाओं ने मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, तथापि इनके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक संरचनात्मक, प्रशासनिक एवं व्यावहारिक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। इन चुनौतियों का समुचित समाधान किए बिना योजनाओं के अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इन प्रमुख चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है—

**(i) प्रशिक्षण और उद्योग की मांग में असंतुलन (Skill Mismatch):** कौशल विकास योजनाओं की सबसे प्रमुख चुनौती प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच असंतुलन है। कई बार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पुराने या अप्रासंगिक होते हैं, जो वर्तमान औद्योगिक मांगों के अनुरूप नहीं होते। परिणामस्वरूप, प्रशिक्षित युवा रोजगार पाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उद्योगों की बदलती तकनीकों और आवश्यकताओं के साथ तालमेल न बैठा पाने से "स्किल गैप" (Skill Gap) उत्पन्न होता है, जो मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग में बाधा बनता है।

**(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी:** राजस्थान के अधिकांश भाग ग्रामीण हैं, जहाँ कौशल विकास योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव है। अनेक युवा इन योजनाओं की जानकारी से वंचित रहते हैं, जिससे वे इनका लाभ नहीं उठा पाते। विशेष रूप से

दूरदराज क्षेत्रों में सूचना का प्रसार सीमित होने के कारण प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुँच भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इससे योजनाओं की पहुँच (Reach) सीमित हो जाती है।

**(iii) प्रशिक्षित युवाओं के लिए सीमित रोजगार अवसर:** यद्यपि कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, लेकिन राज्य में पर्याप्त रोजगार अवसरों का अभाव एक गंभीर चुनौती है। विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उद्योगों की कमी के कारण प्रशिक्षित युवाओं को अपने कौशल के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पाता। इसके परिणामस्वरूप, कई बार युवा अन्य राज्यों की ओर पलायन करने के लिए विवश हो जाते हैं।

**(iv) योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक बाधाएँ:** कई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशासनिक जटिलताएँ भी बाधा उत्पन्न करती हैं। प्रशिक्षण प्रदाताओं की गुणवत्ता, निगरानी प्रणाली की कमजोरी, तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी जैसी समस्याएँ सामने आती हैं। इसके अतिरिक्त, कभी-कभी लाभार्थियों के चयन, प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा प्लेसमेंट की पारदर्शिता को लेकर भी प्रश्न उठते हैं, जो योजनाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं।

(v) **फंडिंग और निगरानी की समस्याएँ:** कौशल विकास योजनाओं के सफल संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और प्रभावी निगरानी प्रणाली की आवश्यकता होती है। कई बार बजट की सीमाएँ, समय पर फंड का आवंटन न होना तथा संसाधनों का असमान वितरण योजनाओं की गति को प्रभावित करता है। साथ ही, निगरानी (Monitoring) एवं मूल्यांकन (Evaluation) की प्रभावी प्रणाली के अभाव में योजनाओं की वास्तविक प्रगति और परिणामों का आकलन करना कठिन हो जाता है।

उपरोक्त चुनौतियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि कौशल विकास योजनाओं की सफलता केवल उनके निर्माण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, उद्योगों के साथ समन्वय, तथा सतत निगरानी पर भी निर्भर करती है। यदि इन चुनौतियों का समाधान योजनाबद्ध एवं समन्वित प्रयासों के माध्यम से किया जाए, तो राजस्थान में कौशल विकास योजनाएँ और अधिक प्रभावी होकर मानव संसाधन विकास को नई दिशा प्रदान कर सकती हैं।

## 11. सुझाव (Suggestions)

राजस्थान सरकार की कौशल विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुख तथा समावेशी बनाने के लिए कुछ ठोस एवं व्यावहारिक सुधारों की आवश्यकता है। ये सुझाव न केवल योजनाओं की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि मानव संसाधन विकास के लक्ष्यों को अधिक व्यापक रूप से प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

**(i) उद्योगों के साथ अधिक समन्वय स्थापित किया जाए:** कौशल विकास कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के कितने अनुरूप हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण संस्थानों, उद्योगों एवं नीति-निर्माताओं के बीच एक सुदृढ़ समन्वय तंत्र विकसित किया जाए। "इंडस्ट्री-इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप" (Industry-Institute Partnership) को बढ़ावा देकर पाठ्यक्रमों को समय-समय पर अद्यतन (Update) किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT), अप्रेंटिसशिप (Apprenticeship) तथा इंटर्नशिप कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाकर युवाओं को व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा सकता है।

**(ii) डिजिटल और उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण बढ़ाया जाए:** वर्तमान युग डिजिटल और तकनीकी परिवर्तन का युग है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए कौशल विकास योजनाओं में इन उभरते क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे युवा भविष्य के रोजगार बाजार के लिए तैयार होंगे और राज्य की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।

**(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाएं:** ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव एक प्रमुख बाधा है। इस समस्या के समाधान के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। पंचायत स्तर पर शिविरों, मोबाइल प्रशिक्षण इकाइयों, डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा स्थानीय मीडिया के माध्यम से युवाओं को योजनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ही, स्थानीय समुदायों एवं स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित कर योजनाओं की पहुँच को बढ़ाया जा सकता है।

**(iv) प्रशिक्षण की गुणवत्ता और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाए:** कौशल विकास योजनाओं की प्रभावशीलता प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसलिए प्रशिक्षण केंद्रों की नियमित निगरानी (Monitoring) एवं मूल्यांकन (Evaluation) के लिए एक सशक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षकों (Trainers) की गुणवत्ता में सुधार, आधुनिक उपकरणों का उपयोग तथा प्रशिक्षण के मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन "आउटकम बेस्ड" (Outcome-based) दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिससे वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जा सके।

**(v) स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई जाए:** कौशल विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल रोजगार प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करना है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता, सब्सिडी, आसान ऋण (Easy Credit) तथा मार्गदर्शन (Mentorship) प्रदान किया जाए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित कर युवाओं को स्टार्टअप एवं व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

उपरोक्त सुझाव यह स्पष्ट करते हैं कि कौशल विकास योजनाओं को केवल प्रशिक्षण तक सीमित न रखकर उन्हें एक समग्र विकास मॉडल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें उद्योग, शिक्षा, वित्त एवं सामाजिक संरचनाओं का समन्वय हो। यदि इन सुधारों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो राजस्थान में कौशल विकास योजनाएँ न केवल मानव संसाधन विकास को सुदृढ़ करेंगी, बल्कि राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को भी नई दिशा प्रदान करेंगी।

## 12. निष्कर्ष (Conclusion)

राजस्थान सरकार की कौशल विकास योजनाएँ राज्य के मानव संसाधन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली पहल के रूप में उभरकर सामने आई हैं। इन योजनाओं ने न केवल युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान किया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, सक्षम एवं प्रतिस्पर्धी बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के युवाओं की रोजगार क्षमता (Employability) में वृद्धि हुई है, जिससे बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायता मिली है तथा आर्थिक गतिविधियों को गति प्राप्त हुई है।

इन योजनाओं का प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। महिलाओं, ग्रामीण युवाओं तथा समाज के वंचित वर्गों को विशेष प्राथमिकता दिए जाने से सामाजिक समावेशन (Social Inclusion) को बढ़ावा मिला है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं को कम करने में सहायता प्राप्त हुई है। साथ ही, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं, जो सतत विकास (Sustainable Development) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास योजनाओं ने औद्योगिक विकास को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया है। प्रशिक्षित एवं कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता से उद्योगों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है, जिससे राज्य में निवेश के अवसर भी बढ़े हैं। इस प्रकार, कौशल विकास और औद्योगिक विकास के बीच एक सकारात्मक संबंध स्थापित हुआ है, जो राज्य की समग्र आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है।

हालांकि, इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अभी भी कुछ चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जैसे—प्रशिक्षण और उद्योग की मांग के बीच असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, तथा सीमित रोजगार अवसर। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक जटिलताएँ एवं निगरानी तंत्र की कमजोरी भी योजनाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि इन समस्याओं का समाधान योजनाबद्ध एवं समन्वित प्रयासों के माध्यम से किया जाए।

भविष्य की दृष्टि से, यह अपेक्षित है कि राजस्थान सरकार कौशल विकास योजनाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाए, जिसमें उद्योगों के साथ गहन सहयोग, डिजिटल एवं उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण, तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता शामिल हो। यदि इन सुधारों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो कौशल विकास योजनाएँ राज्य के मानव संसाधन को और अधिक सशक्त बनाकर राजस्थान को आर्थिक रूप से समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार की कौशल विकास योजनाएँ केवल रोजगार सृजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की आधारशिला हैं, जो राज्य के सतत एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध हो रही हैं।

**संदर्भ (References)**

1. Department of Skill, Employment and Entrepreneurship. (2023). *Annual Report*. Government of Rajasthan.
2. Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation. (2023). *Skill Development Initiatives Report*.
3. National Skill Development Corporation. (2022). *Skill India Report*.
4. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. (2023). *Annual Report*.
5. NITI Aayog. (2022). *Strategy for New India @75*.
6. Government of Rajasthan. (2022). *Economic Review Rajasthan*.
7. Rajasthan Skill Development Policy 2025. (2022). Official Document.
8. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. (2023). Scheme Guidelines.
9. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana. (2023). Programme Guidelines.
10. Directorate General of Training. (2022). *ITI Training Manual*.
11. Planning Commission of India. (2014). *Skill Development in India*.
12. World Bank. (2020). *India Skills Development Report*.
13. International Labour Organization. (2021). *Skills for Employment Policy Brief*.
14. UNESCO. (2020). *Technical and Vocational Education and Training Report*.
15. Asian Development Bank. (2021). *India: Skill Development Program Evaluation*.
16. Sharma, R. (2021). *Skill Development and Employment Generation in Rajasthan*. Journal of Economics.
17. Singh, P. (2020). *Human Resource Development through Skill Training*. Indian Journal of HRM.
18. Meena, K. (2022). *Role of Skill Development in Rural Employment*. Rural Development Review.
19. Verma, S. (2021). *Impact of PMKVY on Youth Employment*. Economic Studies Journal.
20. Khan, A. (2023). *Skill Development Policies in Rajasthan: A Critical Analysis*.
21. Times of India. (2024). *Skill Development Initiatives in Rajasthan*.
22. The Hindu. (2023). *Employment and Skill Development Trends*.
23. Economic Times. (2023). *Skill India Mission Progress*.
24. Business Standard. (2022). *Rajasthan Economic Growth and Skills*.
25. PIB India. (2023). *Press Releases on Skill Development*.
26. Rajasthan Budget Documents. (2023–24). Government of Rajasthan.
27. Employment Exchange Rajasthan Reports. (2022).
28. Census of India. (2011). *Population Data*.
29. NSSO Reports. (2020). *Employment and Unemployment Survey*.
30. Labour Bureau India. (2022). *Employment Statistics*.
31. Skill India Portal. (2023). Government of India.
32. Rajasthan Government Official Website. (2023).
33. NSDC Sector Skill Council Reports. (2022).
34. DDU-GKY Rajasthan Reports. (2023).
35. PMKVY Dashboard Reports. (2023).
36. OECD. (2021). *Skills Strategy Report*.
37. McKinsey Global Institute. (2020). *Future of Work in India*.
38. Deloitte India. (2021). *Skill Development Trends Report*.
39. KPMG India. (2022). *Skill Gap Analysis Report*.
40. EY India. (2021). *Human Capital Development Report*.